नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Wednesday 31st December 2025 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 245 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

आर्थिक पतन टालने को राष्ट्रीय संपत्तियां बेच रहा पाकिस्तान, एयरलाइंस बेचने के बाद अब इनका है नंबर

नई दिल्ली। पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जहां विदेशी कर्ज 134 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। आईएमएफ की शर्तों पर चल रहे निजीकरण अभियान में हाल ही में पीआईएको निजी हाथों में सौंपा गया। अब सरकार बिजली वितरण कंपनियां (DISCOs जैसे IESCO, FESCO), बैंक (First Women Bank, ZTBL), न्यूयॉर्क का Roosevelt Hotel (जॉइंट वेंचर मॉडल से), ऊर्जा संयंत्र और बीमा संस्थाओं को निजीकरण की योजना बना रही है। यह 'करो या मरो' स्थिति है, लेकिन आलोचक इसे कुप्रबंधन छिपाने और राष्ट्रीय संपत्तियों की बिक्री बता रहे हैं।

पीआईए एक लंबे समय से संकटग्रस्त राष्ट्रीय विमानन कंपनी है जो वर्षों से भारी घाटे का सामना कर रही थी। सरकारी दस्तावेजों और कैबिनेट की चर्चाओं से संकेत मिलता है कि बिजली वितरण, बैंकिंग, आतिथ्य, बीमा और ऊर्जा सहित कई सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को 2026 के अंत से पहले निजी हाथों में हस्तांतरित किया जा सकता है।

हाल के महीनों में पाकिस्तान का आर्थिक संकट और गहरा गया है, और विदेशी कर्ज कथित तौर पर 131 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार अब केवल दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज ले रहीहै।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की राहत राशि के लिए बड़े पैमाने पर निजीकरण एक पूर्व शर्त है। विशेषज्ञों का कहना है कि महत्वपूर्ण पुनर्गठन और परिसंपत्तियों की बिक्री के बिना, पाकिस्तान को श्रीलंका के समान ऋण संकट का सामना करना पड़ सकता है।

पाकिस्तान सरकार अगले 12 महीनों में "एजेंडा-5" के तहत पांच क्षेत्रों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। इसमें बिजली वितरण कंपनियां (IESCO, FESCO, GEPCO), बैंकिंग क्षेत्र (फर्स्ट वुमन बैंक, ZTBL), होटल व अचल संपत्ति (रूजवेल्ट होटल, सर्विसेज होटल), घाटे में चल रही ऊर्जा उत्पादन कंपनियां (जेनकोस) और बीमा व यूटिलिटी स्टोर नेटवर्क शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि इससे आर्थिक सुधार और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, जबकि आलोचकों को आशंका है कि इससे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता कमजोर होगी।

ELECTION 2026 | BMC चुनाव 2026: भाई-भतीजावाद की जय!

BMC चुनाव 2026: भाई-भतीजावाद की जय! वार्ड 5 के लिए 5 घंटे तक संघर्ष, शिंदे-फडणवीस के नेता अड़े, 3 सीटों पर अदला-बदली

मुंबई | मुंबई: मुंबई महानगरपालिका में ठाकरे भाइयों और बीजेपी-शिंदेसेना के बीच मुकाबला होने वाला है। महायुति की सीटों का बंटवारा नामांकन करने से कुछ घंटे पहले ही तय हुआ। इसके मुताबिक, बीजेपी 137 और शिंदेसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई महानगरपालिका में 227 सीटें हैं। महायुति ने एक वार्ड के लिए 5 घंटे तक लड़ाई लड़ी। दो विधायकों ने अपने परिवार के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस वजह से दो आम कार्यकर्ताओं की कुर्सी चली गई।

वार्ड नंबर 5 में क्या विवाद?

वार्ड नंबर 5 मगठाणे विधानसभा क्षेत्र में आता है। शिंदेसेना के प्रकाश सुर्वे यहां से विधायक हैं। वे 2014 से चुनाव लड़ रहे हैं। वे अपने बेटे राज सुर्वे के लिए वार्ड नंबर 5 चाहते थे। इसलिए वे अटक गए। दूसरी ओर विधान परिषद में बीजेपी के ग्रुप लीडर प्रवीण दारेककर अपने भाई प्रकाश दारेककर पर अड़े हुए थे।

इस वजह से वार्ड नंबर पांच के लिए शिंदेसेना और बीजेपी के बीच कड़ी खींचतान हुई। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना से शिंदे सेना में शामिल हुए पूर्व पार्षद संजय घाडी भी वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने के लिए बेताब थे। इसके लिए उन्होंने पिछले कई महीनों से वार्ड में काम करना शुरू कर दिया था।

एक वार्ड से तीन-तीन दावेदार

क्योंकि एक वार्ड के लिए तीन-तीन उम्मीदवार थे और दोनों पार्टियां अड़ी हुई थीं, इसलिए एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। आखिर में यह सीट शिंदे सेना के पास चली गई। विधायक प्रकाश सुर्वे ने अपनी बेटी के लिए यह सीट छीन ली। इस वजह से संजय घाडी बाहर हो गए। लोकल पार्षद घाडी के लिए वार्ड छोड़ने का समय आ गया था। उन्हें अब वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ना होगा।

वार्ड-4 पर किसने मारी बाजी?

मंगेश पंगारे इस बात से परेशान हैं कि संजय घाडी वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ेंगे। मंगेश पंगारे शिंदे सेना के सब-डिविजनल हेड हैं। वे वार्ड नंबर 4 से तैयारी कर रहे थे। वे वार्ड नंबर 4 से टिकट पाने के लिए शिंदे सेना में शामिल हुए थे। जैसे ही प्रकाश सुर्वे ठाकरे छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हुए, पंगारे भी शिंदे सेना में शामिल हो गए। उस समय उन्होंने वार्ड नंबर 4 से शपथ ली थी। लेकिन अब जब संजय घाडी वार्ड नंबर 5 छोड़कर 4 में आ गए हैं, तो पंगारे मुश्किल में हैं।

प्रवीण दारेककर क्यों अड़े?

विधान परिषद में बीजेपी के ग्रुप लीडर प्रवीण दारेककर इस बात पर अड़े थे कि उनके भाई को वार्ड नंबर 5 से नॉमिनेट किया जाए। चूंकि यह सीट शिंदे सेना के राज सुर्वे के लिए खाली हो गई, इसलिए प्रकाश दारेककर वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ेंगे। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई। यहां शिंदे सेना के बालकृष्ण ब्रेथ एक गेम बन गए हैं। वे पहले के कॉर्पोरेटर हैं।

पीएम मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर जताया गहरा शोक, एस. जयशंकर ढाका में उनके अंतिम संस्कार में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे बीते कई दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। उनके निधन की खबर से ढाका और पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है और बांग्लादेश में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उनके परिवार और बांग्लादेश के लोगों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त की हैं और उनके योगदान को याद किया है। मोदी ने कहा कि वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा।

भारत सरकार ने फैसला किया है कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 31 दिसंबर को ढाका जाकर उनके अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्मान और संबंधों की महत्ता को दर्शाता है। खालिदा जिया के निधन के साथ ही दक्षिण एशियाई राजनीति में एक युग समाप्त हो गया है और विभिन्न देशों के नेताओं ने सम्मान और श्रद्धांजलि व्यक्त की है।

अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट: 2026 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष की आशंका, आतंकवाद को मुख्य कारण बताया

नई दिल्ली। अमेरिका के प्रतिष्ठित थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) की हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष फिर उभर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत-पाक सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि जारी रहती है, तो दोनों देशों के बीच तनाव सैन्य टकराव में बदल सकता है। यह आशंका विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों को ध्यान में रखकर जताई गई है।

रिपोर्ट 'Conflicts to Watch in 2026' में इस संभावना को मध्यम श्रेणी की संभावना बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है, तो संघर्ष का असर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर खतरा बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि तनाव के फैलने की स्थिति में इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, खासकर वैश्विक सुरक्षा पर असर संभव है।

विश्लेषकों के अनुसार, पिछले वर्षों में सीमा पर झड़पें और आतंकवादी घटनाओं से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, और अगर कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो यह स्थिति और जटिल हो सकती है। CFR की रिपोर्ट ने यह भी चेताया है कि सीमा तनाव और आतंकवाद के कारण संघर्ष की आशंका नकारा नहीं जा सकता।

इसके अलावा, रिपोर्ट ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर भी संघर्ष की संभावना पर चर्चा की है, लेकिन उसका व्यापक असर कम बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक संवाद और सुरक्षा उपायों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि दोनों परमाणु शक्तियों के बीच किसी बड़े सैन्य टकराव को टाला जा सके।

IndiGo को लगा बड़ा झटका, लगा 458 करोड़ का GST जुर्माना, पेनल्टी को चुनौती देगी कंपनी

संवाददाता |

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन इंडिगो को जीएसटी विभाग से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली दक्षिण सीजीएसटी कमिश्नरेट ने कंपनी पर 458.26 करोड़ रुपये का डिमांड ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश केंद्रीय जीएसटी एक्ट की धारा 74 के तहत FY2018-19 से 2022-23 के दौरान विदेशी सप्लायर से प्राप्त मुआवजे पर टैक्स, ब्याज, पेनल्टी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़ा है।

इंटरग्लोब एविएशन ने इसे कानून के अनुरूप न बताते हुए कहा कि वह अपील दायर करेगी। कंपनी के अनुसार, इस आदेश से उसकी वित्तीय स्थिति या परिचालन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। वहीं, लखनऊ सीजीएसटी ने FY2021-22 के लिए 14.59 लाख रुपये की पेनल्टी भी लगाई है। एविएशन सेक्टर में जीएसटी जांच पर बहस तेज हो गई है।

मणिपुर हिंसा: लगभग 10,000 विस्थापितों का पुनर्वास पूरा, मुख्य सचिव ने बताया प्रगति

मणिपुर (इंफाल)। मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण राज्य में विस्थापित हुए लगभग 10,000 लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है, यह जानकारी मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा 2025-26 के मणिपुर बजट में ₹573 करोड़ के पुनर्वास पैकेज के तहत चरणबद्ध पुनर्वास कार्य किए गए हैं।

गोयल ने कहा कि अब तक 2,200 से अधिक परिवारों (लगभग 10,000 लोग) को फिर से बसाया गया है और 4,000 और घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। सहायता में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी शामिल हैं।

मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 260 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए थे। हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और हाल में हिंसा में कमी आई है।

मुख्य सचिव ने प्रभावितों के कल्याण और गरिमा की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है, साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने की दिशा में कदम जारी हैं।

'अवैध घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालेंगे', बंगाल में शाह ने भरी हुंकार; ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप

'अवैध घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालेंगे'

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा अवैध बांग्लादेशियों को मुख्य मुद्दा बनाएगी। दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि अवैध घुसपैठ सिर्फ बांग्ला अस्मिता के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद इन घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा और बांग्ला अस्मिता को फिर से बहाल किया जाएगा।

पिछले 10 वर्षों के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बंगाल में भाजपा को मिले मतों और सीटों का हवाला देते हुए शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत के साथ जीत का दावा किया। कहा कि भाजपा की सरकार ऐसा सुरक्षा ग्रिड तैयार करेगी कि सीमा पार से परिंदा भी पर नहीं मार सके। अमित शाह ने घुसपैठ रोकने में नाकामी के लिए बीएसएफ की नाकामी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी के तृणमूल कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब दिया।

घुसपैठ को प्रश्रय देने का आरोप

शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधे-सीधे घुसपैठ को प्रश्रय देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के बार-बार कहने के बावजूद सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह खुद सात बार राज्य सरकार को पत्र लिख चुके हैं और केंद्रीय गृह सचिव तीन बार राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

अवैध तरीके से सीमा पार करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राज्य प्रशासन उन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराकर वैध बनाने की कोशिश करता है। शाह ने बताया कि असम और त्रिपुरा में भाजपा की सरकारें अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने में सफल रही हैं। उन्होंने बंगाल की जनता से अवैध घुसपैठियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की अपील की।

बंगाल में 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या

अमित शाह ने ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन को भय, भ्रष्टाचार और कुशासन का पर्याय बताया। कहा कि तृणमूल ने वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया है। बंगाल में 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं के पलायन के लिए मजबूर होने का हवाला देते हुए शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने इसे बदलने का मन बना लिया है।

उन्होंने बताया कि पहले वामपंथी और फिर तृणमूल सरकार के चार दशक के लंबे कार्यकाल में कैसे बंगाल आर्थिक विकास में पिछड़ता चला गया। 7000 से अधिक उद्योग राज्य से पलायन कर चुके हैं। कटमनी (रंगदारी) व भ्रष्टाचार के कारण बंगाल के विकास की गति रुक गई है। भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल का खोया गौरव पुन: स्थापित किया जाएगा और महान विचारकों द्वारा परिकल्पित 'सोनार बांग्ला' (स्वर्णिम बंगाल) का निर्माण किया जाएगा।

मतुआ समुदाय को दिया आश्वासन

अमित शाह ने बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण बंगाल आए मतुआ समुदाय के शरणार्थियों को पूरी तरह से सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। कहा कि शरणार्थी मतुआ समुदाय को एसआईआर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक भाजपा है, ममता बनर्जी मतुआ समुदाय का कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं।

उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप लगाया। उन्होंने तृणमूल के मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सूची भी गिनाई। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को अपने मंत्रियों के यहां से करोड़ों रुपये नकदी की बरामदगी क्यों नहीं दिखती है।

ठाणे नगरपालिका: शिंदे गुट के मंत्री के बेटे पूर्वेश सरनायक का बड़ा फैसला- "राजा का बेटा नहीं, हकदार बने"

ठाणे (महाराष्ट्र)। आगामी ठाणे महानगरपालिका चुनाव के बीच शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेता और मंत्री प्रताप सरनाइक के बेटे पूर्वेश सरनाइक ने एक अहम राजनीतिक कदम उठाया है। उन्होंने वार्ड नंबर 14 से इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है और स्पष्ट किया है कि "राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा।" यह बयान वंशवादी राजनीति के बजाय पात्रता और कड़ी मेहनत को महत्व देने की सोच को दर्शाता है।

पूर्वेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि 2017 में उन्हें इसी वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन भारी मतों के बावजूद वह जीत हासिल नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक "आशीर्वाद" जैसा था और अब उन्होंने शिवसेना के एक कार्यकर्ता को मौका देने का निर्णय लिया है, जो जमीनी स्तर पर पार्टी के विचारों और सेवा को आगे बढ़ा सके। उन्होंने यह निर्णय लगभग छह महीने पहले सोच-समझकर लिया और पार्टी की वरिष्ठ नेतृत्व को पहले ही सूचित किया था।

पूर्वेश ने यह भी कहा कि भले ही वह इस चुनाव में उम्मीदवार न हों, लेकिन पार्टी के साथ सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे और जनता की सेवा जारी रखेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों, शिवसैनिकों और वोटर्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका प्यार और भरोसा ही उनकी शक्ति है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला शिंदे गुट की लोकल राजनीति के भीतर कार्यकर्ताओं को अवसर देने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है और इससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल सकती है। ठाणे महानगरपालिका में कुल 131 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें विभिन्न दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा अनुमानित है।

यह निर्णय राजनीतिक समीकरणों और स्थानीय कार्यकर्ता-आधारित नेतृत्व की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब सभी दल आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं।

नामांकन खत्म, नांदेड का सब्र भी खत्म : पानी, जलभराव और बदहाली पर सत्ता से सीधे सवाल?

संपादकीय... |

गोदावरी के पवित्र तट पर बसा नांदेड कोई साधारण शहर नहीं है। यह वही धरती है जहां तख़्त श्री हज़ूर साहिब जैसी महान धार्मिक धरोहर स्थित है, जहां देश-विदेश से श्रद्धालु नतमस्तक होने आते हैं। यही नांदेड गोदावरी और आसना नदी के प्रवाह से जुड़ा है और यहीं विष्णुपुरी बांध जैसा महत्वपूर्ण जलस्रोत मौजूद है, जो पूरे शहर की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त माना जाता है।
इतनी प्राकृतिक, धार्मिक और जलसंपदा से समृद्ध होने के बावजूद यदि यह शहर आज पानी, जलभराव और अव्यवस्था से जूझ रहा है, तो यह केवल दुर्भाग्य नहीं—यह सत्ता की विफलता का प्रमाण है।

30 दिसंबर 2025 को नांदेड–वाघाळा महानगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। शहर में चुनावी हलचल तेज है, झंडे-बैनर लग चुके हैं और एक बार फिर “विकास” के दावे गूंजने लगे हैं। लेकिन नांदेड की जनता के मन में आज एक ही सवाल है—क्या इस बार भी शहर की असली पीड़ा को नजरअंदाज कर वोट मांगे जाएंगे?

नांदेड की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विष्णुपुरी बांध जैसे मजबूत जलस्रोत के बावजूद नागरिकों को नियमित पानी नहीं मिल रहा। कई इलाकों में यह है कि तीन दिन में एक बार, यानी सप्ताह में केवल दो दिन नलों में पानी छोड़ा जा रहा है। यह तब है, जब गोदावरी नदी बह रही है और बांध में पानी मौजूद है। सवाल सीधा है—जब पानी है, तो जनता को क्यों नहीं मिल रहा?
यह जलसंकट प्राकृतिक नहीं, पूरी तरह प्रशासनिक और राजनीतिक नाकामी का नतीजा है।

पानी की किल्लत ही नहीं, नांदेड के कई इलाके हर साल बरसात में जलमग्न हो जाते हैं। सलम एरिया, देगलूर नाका की नई बस्तियां, मिल एरिया,खडकपुरा की कई बस्तियां, सैलाब नगर, श्रावस्तीनगर,गंगा चाल,पक्की चाल,समीरा बाग, जैसे क्षेत्र थोड़ी-सी बारिश में ही तालाब बन जाते हैं। पानी घरों में घुस जाता है, घरेलू सामान खराब होता है और आम नागरिक हर साल वही त्रासदी झेलता है।
यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन हर साल सत्ता खामोश रहती है और अगली बारिश तक मामला भुला दिया जाता है।

इन इलाकों में नालियों और सड़कों की हालत बदतर है। कई जगह नालियां टूटी हुई हैं, कई जगह पूरी तरह गायब हैं और अनेक नई बस्तियों में तो आज तक न पक्की नालियां बनी हैं, न ढंग की सड़कें। बारिश का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, नतीजा—गंदगी, मच्छर, बीमारियां और नारकीय जीवन।
यह किसी एक वार्ड की नहीं, बल्कि पूरे नांदेड शहर की सच्चाई है।

सबसे बड़ा और सबसे असहज सवाल यह है कि जब हर साल यही समस्याएं सामने आती हैं, तो अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ?
क्या नगरसेवकों की जिम्मेदारी केवल चुनाव जीतने तक सीमित है?
क्या महापौर, प्रशासन और सत्ताधारी दलों की जवाबदेही सिर्फ भाषणों तक है?

चुनाव से ठीक पहले शहर की कई मुख्य सड़कों पर रातों-रात खुदाई और काम शुरू कर दिए गए हैं। अधूरे और जल्दबाजी में किए गए इन कार्यों से नांदेड में ट्रैफिक की समस्या विकराल हो गई है। सुबह-शाम जाम आम हो गया है, एंबुलेंस तक फंस रही हैं। सवाल यह है—ये काम सालभर क्यों नहीं हुए?
चुनाव आते ही शहर को खोदना क्या विकास है, या सिर्फ दिखावा?

नामांकन के अंतिम दिन यह भी साफ हो गया कि वही पुराने चेहरे, वही पुराने दल और वही पुरानी कार्यशैली फिर मैदान में है। टिकट वितरण में भी जनता की पीड़ा नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरण और निजी हित हावी नजर आए। जिन इलाकों में वर्षों से पानी, सड़क और जलनिकासी की समस्या है, वहां भी उन्हीं प्रतिनिधियों को दोबारा मौका दिया गया—जिनका रिकॉर्ड नाकामी से भरा है।

यह चुनाव अब केवल नगरसेवक चुनने का नहीं रहा। यह नांदेड की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार सत्ता से हिसाब मांगने का अवसर है। जनता को तय करना होगा कि वह फिर बहकावे में आएगी या इस बार सवाल पूछेगी—
पानी क्यों नहीं मिलता?
हर साल घरों में बारिश का पानी क्यों घुसता है?
नालियां और सड़कें अब तक क्यों नहीं बनीं?

अगर इस बार भी जनता चुप रही, तो आने वाले पांच साल भी यही बदहाली, वही जलभराव और वही शिकायतें दोहराई जाएंगी।
नामांकन समाप्त हो चुका है—अब बहानों का समय भी समाप्त होना चाहिए।

नांदेड को भाषण नहीं, समाधान चाहिए।
नांदेड को वादे नहीं, जवाब चाहिए।

और सत्ता को यह समझ लेना चाहिए—
इस बार नांदेड चुप नहीं बैठेगा।

IndiaVSPak | 2026 में भारत-पाकिस्तान में युद्ध की आशंका

2026 में भारत-पाकिस्तान में युद्ध की आशंका, अमेरिकी थिंक टैंक ने दी चेतावनी, कश्मीर से कनेक्शन जानें

वॉशिंगटन: अमेरिका की एक थिंक टैंक ने 2026 में भारत और पाकिस्तान में सशस्त्र संघर्ष की आशंका जताई है। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों का सर्वे करने वाले इस थिंक टैंक ने कहा है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सशस्त्र संघर्ष में बदल सकते हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) ने सशस्त्र संघर्ष की संभावना को "मध्यम" बताया है। उसने यह भी आशंका जताई है कि इसका अमेरिकी हितों पर असर पड़ सकता है।

CFR की रिपोर्ट में क्या कहा गया है

CFR ने अपनी 'कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026' रिपोर्ट में कहा है कि "बढ़ी हुई आतंकवादी गतिविधि के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सशस्त्र संघर्ष की 'मध्यम संभावना' है।" यह रिपोर्ट तब प्रकाशित हुई है, जब मई में भारत-पाकिस्तान के बीच चार दिनों का सशस्त्र संघर्ष हो चुका है।

इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए थे। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बाद में यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान की सेनाओं तक पहुंच गया।

एलओसी पर तनाव
उस दौरान भारत के जवाबी कार्रवाई से परेशान पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की पहल की थी। लेकिन, वह लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है। पाकिस्तानी सेना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज असीम मुनीर के नेतृत्व में लगातार जंगी तैयारियां कर रही है।

इसके अलावा खुफिया इनपुट है कि इस सर्दी जम्मू क्षेत्र में 30 से अधिक पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। ऐसे में भारत ने भी इस इलाके में सुरक्षा को मजबूत किया है। पाकिस्तान के पीओके में कई आतंकी लॉन्चपैड को फिर से सक्रिय कर दिया है। इन लॉन्चपैड में दर्जनों आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी में हैं।

भारत-पाकिस्तान खरीद रहे हथियार
भारत और पाकिस्तान में भले ही युद्धविराम लागू है, लेकिन सीमा पर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद में तेजी दिखाई है। भारत ने हाल में ही ड्रोन, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, गाइडेड बमों की खरीद के लिए 79000 करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी दी है। इस तरह पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी कमियों को दूर करने के लिए कई देशों से हथियारों की खरीद की है। पाकिस्तान ने सैन्य हथियार मुख्य रूप से चीन और तुर्की जैसे देशों से खरीदा है।

WORLD NEWS | सऊदी अरब-संयुक्त अरब अमीरात तनाव

सऊदी अरब-संयुक्त अरब अमीरात तनाव से भारत परेशान क्यों, जानें खाड़ी देशों में क्या-क्या दांव पर लगा

● NEWS AGENCY

रियाद: सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इसका प्रमुख कारण सऊदी अरब की यमन में की गई बमबारी है। सऊदी अरब ने यह बमबारी यमन के बंदरगाह शहर मुकाला पर की। सऊदी ने बताया कि इस दौरान एक अलगाववादी संगठन के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाया गया। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव पर भारत करीबी नजर बनाए हुए है। भारत को आशंका है कि अगर इन दोनों खाड़ी देशों में टकराव बढ़ता है तो इसके तुरंत और दूरगामी परिणाम होंगे। इन दोनों देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। इनके अलावा सऊदी अरब और यूएई से भारत के करीबी संबंध भी हैं।

भारत यूएई संबंध
कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के साथ मजबूत संबंध हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। यूएई के साथ भारत की करीबी रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देश रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोगी भी हैं। इनके अलावा, दोनों देश भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) का भी हिस्सा हैं, जो भारत को यूरोप से जोड़ता है। भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका I2U2 फ्रेमवर्क में भी शामिल हैं। भारत ऊर्जा आयात को लेकर भी यूएई के साथ करीबी संबंध बनाए हुए है, भले ही इसकी मात्रा बाकी सप्लायर्स के मुकाबले कम है।
भारत सऊदी अरब संबंध

भारत के सऊदी अरब के साथ भी गहरे रिश्ते हैं। दोनों देश रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूती से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऊर्जा, निवेश, क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोगकर्ता हैं। सऊदी अरब को भारत का सिर्फ तेल सप्लायर के तौर पर नहीं, बल्कि एक लंबे समय के आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखा जाता है। सऊदी अरब भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। भारत भी सऊदी अरब की खाद्य सुरक्षा और कुशल कार्यबल में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध भी मजबूत हो रहे हैं।

सऊदी अरब-यूएई तनाव से भारत क्यों परेशान
सऊदी अरब और यूएई के साथ मजबूत संबंध भारत को विशेष तौर पर संवेदनशील बनाते हैं। अगर इन दोनों देशों में तनाव बढ़ता है तो इसका असर यमन, लाल सागर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर भी देखने को मिलेगा, जहां भारत के हित जुड़े हुए हैं।

सऊदी अरब-संयुक्त अरब अमीरात तनाव

भारत के लिए, बाब-अल-मंडेब और आस-पास के समुद्री रास्ते सिर्फ रणनीतिक स्थान ही नहीं हैं, बल्कि लाइफलाइन है, जहां से ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और सुरक्षा संबंधी नौवहन होता रहता है। भारत 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी से होकर आता है। लाल सागर या अरब सागर में कोई भी रुकावट माल ढुलाई की लागत बढ़ा सकती है और ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा सकती है।

भारतीय कामगारों पर होगा असर

खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में निवास करती है। उनके सुरक्षा और हित दोनों देशों में स्थिरता से जुड़ा है। अगर दोनों देशों में संघर्ष छिड़ता है, तो इसका सीधा असर भारतीय कामगारों पर पड़ेगा। यही कारण है कि भारत की प्राथमिकता दोनों देशों में तनाव कम करने और बातचीत शुरू करने की है। भारत किसी भी सूरत में सऊदी अरब और यूएई के बीच किसी एक का पक्ष नहीं लेगा। हालांकि, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रक्षा समझौते से भारत के लिए चिंता जरूर बढ़ गई है। वहीं, चीन भी इन दोनों देशों में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका भी परेशान है।

Top News यमन से सभी सैनिकों को वापस बुलाएंगे,

यमन से सभी सैनिकों को वापस बुलाएंगे, नहीं भेजे थे हथियार... यूएई का पलटवार, सऊदी को इशारों में चेताया

अबू धाबी: सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर यमन में अलगाववादियों के हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूएई ने संयम व समझदारी बतरने की अपील की है। उसने सऊदी अरब के आरोपों को नकार दिया है। यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर सऊदी अरब के हवाई हमले करने के बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। यूएई ने यह भी कहा है कि वह यमन से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाएगा।
सऊदी अरब ने हथियार भेजने से इनकार किया
सऊदी अरब का कहना है कि यूएई ने वहां बख्तरबंद वाहन और हथियार भेजे थे। यूएई ने हथियार भेजने के आरोप से इनकार किया, लेकिन वाहनों की खेप भेजने की बात स्वीकार की। यूएई ने कहा कि ये वाहन उसकी अपनी सेनाओं के लिए थे, हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। यूएई ने इससे पहले ही यमन से अपनी सेनाओं को काफी हद तक वापस बुला लिया था।
सऊदी के खिलाफ किसी कोशिश का हिस्सा नहीं
UAE के विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि देश सऊदी अरब को कमजोर करने की किसी भी क्षेत्रीय कोशिश का हिस्सा नहीं है। बयान में कहा गया, "UAE यमनी पार्टियों के बीच तनाव में उसे शामिल करने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह से खारिज करता है और किसी भी यमनी पार्टी पर दबाव डालने या उसे सैन्य अभियान चलाने का निर्देश देने के आरोपों की निंदा करता है, जो सऊदी अरब की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं या उसकी सीमाओं को निशाना बनाते हैं।" उसने आगे कहा, "संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब की सुरक्षा और स्थिरता के प्रति अपनी लगातार प्रतिबद्धता, उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरे सम्मान और किंगडम या क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को खारिज करने की पुष्टि करता है।"
यूएई ने यमन में सैनिकों की तैनाती पर यह कहा
UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा, "संयुक्त अरब अमीरात 2015 से यमन में वैधता का समर्थन करने, आतंकवादी संगठनों से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग देने और मित्रवत देश यमन के लिए सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए अरब गठबंधन में शामिल रहा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सपूतों ने महान बलिदान दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों ने आधिकारिक तौर पर तय किए गए कार्यों को पूरा करने के बाद 2019 में यमन गणराज्य में अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी। शेष उपस्थिति आतंकवाद-विरोधी प्रयासों के अंतर्गत विशेष टीमों तक सीमित थी और संबंधित अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के समन्वय में कार्यरत थी।"

सैनिकों को वापस बुलाएगा यूएई
बयान में आगे कहा गया "रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और संबंधित साझेदारों के समन्वय से, यमन में शेष आतंकवाद-विरोधी टीमों को अपनी इच्छा से समाप्त करने की घोषणा की है। यह उपाय वर्तमान चरण की आवश्यकताओं के व्यापक मूल्यांकन के ढांचे के अंतर्गत आता है, और यह क्षेत्र की सुरक्षा क्षमता को समर्थन देने में संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धताओं और उसकी भूमिका के अनुरूप है।"

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

नंदिग्राम टाईम्स

Wednesday 31st December 2025 वर्ष - 9 , अंक 245 , पृष्ठ 03

महाराष्ट्र सरकार बड़ा फैसला: शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब एमपीएससी के अधिकार में

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शालेय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए इसका संपूर्ण दायित्व महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा आयोग (MPSC) के हाथ में दे दिया है। यह निर्णय राज्य भर में शिक्षण आयुक्त कार्यालय पर पड़े भारी प्रशासनिक दबाव को कम करने और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

पहले, पवित्र पोर्टल के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा, बुद्धिमत्ता तथा अभियोग्यता चाचणी के बाद पदों की शिफारस तक का काम शिक्षण आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित होता था, जिससे अन्य नीति-निर्माण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर दबाव बन रहा था। इस बदलाव के तहत अब टीईटी, बुद्धिमत्ता चाचणी सहित भर्ती से जुड़ा पूरा आयोजन, परीक्षा संचालन और चयन प्रक्रिया एमपीएससी द्वारा ही संभाली जाएगी।

सरकार का कहना है कि यह कदम भर्ती प्रक्रिया को एक ही स्वायत्त संस्था के अधीन लाकर निर्णय-निर्धारण में तेजी, मानकीकरण व जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इस व्यवस्था के साथ ही भर्ती के दौरान होने वाली प्रशासनिक देरी और लंबी प्रक्रिया से भी छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, एमपीएससी पहले से ही अनेक सरकारी परीक्षा और चयन प्रक्रियाओं का संचालन करती है, इसलिये शिक्षक भर्ती का जिम्मा देना भर्ती प्रणाली में अनुशासन और गुणवत्ता की भरोसेमंदता बढ़ा सकता है।

हालांकि यह बदलाव तुरंत भर्ती प्रक्रिया पर असर नहीं डालेगा, पर आने वाले शिक्षक भर्ती सत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने की संभावना है। इससे नए उम्मीदवारों के लिए एक केंद्रित और पूर्वानुमेय चयन व्यवस्था विकसित होने की उम्मीद है।

सरकार का यह निर्णय राज्य में शिक्षक भर्ती प्रणाली को और अधिक समकालीन, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

BMC ELECTION 2026 | BMC Election 2026: कहीं मिले दिल तो कहीं पर टूटे

BMC Election 2026: कहीं मिले दिल तो कहीं पर टूटे, सत्ताधारी महायुति की महाविकास अघाड़ी से टक्कर, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर?

मुंबई | मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 का राजनीतिक मैदान पूरी तरह गरमा चुका है, जहाँ सत्ताधारी महायुति (बीजेपी-शिवसेना) और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) के घटकों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी, 2026 को वोटिंग और 16 जनवरी को मतगणना तय होने के साथ अब सभी दलों की नज़र निर्णायक नतीजों पर टिकी है।

महायुति में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सीट-शेयरिंग फॉर्मूला अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत 227 सदस्यीय BMC में बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चुनावी गठबंधन में सीटों का यह बंटवारा लंबे समय तक खींचतान के बाद तय हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों दलों ने मिलकर रणनीति को अंतिम रूप दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी की है, जिसमें कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है, जबकि शिवसेना (Uddhav Thackeray) ने मराठी मानुस पर अपना फोकस रखते हुए अधिकांश टिकट मराठी चेहरों को दिए हैं — यह रणनीति स्थानीय पहचान को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

विपक्षी मोर्चे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ तालमेल बिठाया है, जिससे विरोधी खेमे की रणनीति में बदलाव आया है। इसके अलावा कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) ने गठबंधन कर BMC चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास किया है। वहीं शरद पवार की NCP ने अलग-अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और अपनी उम्मीदवार सूची जारी की है, जिससे विपक्ष में कई मोर्चे खुलते दिख रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार महायुति की जीत की संभावनाएँ अभी भी मजबूत हैं, लेकिन विपक्षी दलों की संयुक्त रणनीति इस चुनाव को और भी रोचक बनाती है। महायुति के लिए BMC चुनाव न सिर्फ मुंबई के प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण का प्रश्न है, बल्कि 2026 के आगे होने वाले राजनीतिक मुकाबलों के लिए संकेत भी देगा।

नामांकन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर को पूरी हो चुकी है और अब सभी पार्टियाँ 15 जनवरी की वोटिंग और 16 जनवरी की मतगणना पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस चुनाव के नतीजे मुंबई की राजनीति के साथ-साथ राज्य की राजनीतिक तस्वीर को भी आकार देंगे।

बीएमसी चुनाव 2026: महायुति से आरपीआई का बहिष्कार, रामदास आठवले का बड़ा ऐलान- 38 सीटों पर स्वतंत्र मुकाबला

मुंबई। आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव 2026 से पहले महायुति गठबंधन में सीट-शेयरिंग विवाद उभर आया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने नाराज़गी जताई है कि आरपीआई (आठवले) को बीजेपी-शिवसेना के बीच महायुति सीट-शेयरिंग समझौते में शामिल नहीं किया गया, जिसे उन्होंने "विश्वासघात" बताया है।

आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी ने 26 सीटों की सूची पहले ही गठबंधन को दी थी और अपेक्षा थी कि कम से कम 14-15 सीटें आरपीआई को मिलेंगी, लेकिन उन्हें केवल कुछ सीटें देर रात ऑफर की गईं, जिन पर उम्मीदवार खड़ा करना संभव नहीं था।

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि महायुति के प्रति निष्ठा बनी रहेगी, लेकिन इस चुनाव में आरपीआई 38 सीटों पर स्वतंत्र रूप से "फ्रेंडली फाइट" के साथ उम्मीदवार उतारेगी और शेष सीटों पर वे भाजपा और शिवसेना का समर्थन करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह विवाद महायुति की चुनावी रणनीति में असंतोष को दर्शाता है और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच संगठनात्मक दबाव बढ़ा सकता है।

बर्फ में बदल गया वासुकि ताल, नए साल की शुरुआत बर्फ़बारी से

संवाददाता | दतिया

5G टेलीकॉम सर्विसेज जैसे अधिक हाई स्पीड वाला इंटरनेट संपर्क प्रदान करने में सक्षम इन एयरवेव की नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन शुक्रवार को कम से कम चार आवेदकों के साथ बंद हुए। अडानी ग्रुप ने 8 जुलाई को अपनी रुचि जमा की है। ये नीलामी 26 जुलाई को होनी है। मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र की तीन निजी कंपनियों - जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने आवेदन किया है।5G । मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र की तीन निजी कंपनियों - जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने आवेदन किया है।5G। मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र की तीन निजी कंपनियों -

मीरा-भायंदर चुनाव: भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह का बयान- "इतने पारसद चुनेंगे कि उत्तर भारतीय महापौर बनें"

मीरा-भायंदर (ठाणे)। आगामी महाराजा महानगरपालिका (MBMC) चुनाव 2026 से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह ने मीरा-भायंदर में बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा इतने नगरसेवक (पारसद) चुनाव जीतकर लाएगी कि उत्तर भारतीय महापौर का पद सुनिश्चित किया जा सके। उनका यह बयान स्थानीय राजनीतिक पटल पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से उत्तर भारतीय मतदाताओं से समर्थन की अपील की है।

कृपाशंकर सिंह ने कहा कि यह 29 महापालिकाओं में होने वाली नगरपालिका चुनावों की नौवीं सार्वजनिक चुनावी लड़ाई है और जनता जल्दी से चुनाव करवाए जाने की मांग कर रही थी। उन्होंने यह भरोसा जताया कि भाजपा-महायुति गठबंधन इन सभी महापालिकाओं में सत्ता हासिल करेगा और मीरा-भायंदर में भी मजबूत प्रदर्शन करेगा। इसी बहाने, उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा इतने पारसद चुनने पर ध्यान देगी कि उनके समर्थन से एक उत्तर भारतीय महापौर चुना जा सके।

अपने संबोधन में सिंह ने "नकली शिवसेना" की आलोचना करते हुए कहा कि अब केवल भाजपा के साथ "असली शिवसेना" है और उनकी चुनावी रणनीति हिंदुत्व और विकास पर आधारित है। उन्होंने प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को मजबूत बताया और कहा कि उनके "विकास बुलडोज़र" की तरह कोई भी विकास की राह में नहीं टिक पाएगा।

भाजपा के स्थानीय नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट किया कि वे मीरा-भायंदर में अलग-अलग समुदाय सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन कर रहे हैं ताकि पार्टी के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुँचाया जा सके। मीरा-भायंदर में पहले भी कई बार उत्तर भारतीयों के महापौर चुने जाने का उदाहरण रहा है, जिसे भाजपा ने इस चुनाव में अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में उजागर किया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा की यह अपील भ निराला समर्थन जुटाने और स्थानीय राजनीति में समुदाय आधारित वोटबैंक को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है, जो चुनाव के परिणामों पर असर डाल सकता है।

टि.सी.हरवली आहे

माझी शेख हमीद शेख वहीद या नावाची जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,दुधड तालुका हिमायतनगर जिल्हा नांदेड या शाळेची 5 वी ची टि.सी. हिमायतनगर ते निजामाबाद एस टी बस ने प्रवासात गहाळ झाली आहे. कोणास सापडल्यास खालील पत्यावर आणून द्यावी. आणून देणाऱ्यास योग्य ते बक्षिस देण्यात येईल.

संपर्क करें
शेख हमीद शेख वहीद,
रा.ऑटो नगर, निजामाबाद
ता.जि. निजामाबाद
मो. नंबर (+91 96761 03155)

महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव 2026: भाजपा-शिंदेसेना गठबंधन टूटा, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे में चार-तरफा मुकाबला संभव

मुंबई | महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों से पहले भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच महायुति गठबंधन में बड़े राजनीतिक फूट के संकेत सामने आ रहे हैं, जिससे छत्रपति संभाजीनगर और पुणे महानगरपालिका (PMC) में दोनों पक्षों का स्वतन्त्र मुकाबला संभव दिख रहा है। छत्रपति संभाजीनगर महापालिका चुनाव से पहले भाजपा-शिंदेसेना की महायुति गठबंधन टूटने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। शिंदेसेना के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि युती को भाजपा के स्थानीय नेताओं के अहंकार के कारण नुकसान उठाना पड़ा और इसलिए शिवसेना "स्वबळावर" चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा के नेता भागवत कराड ने दावा किया कि

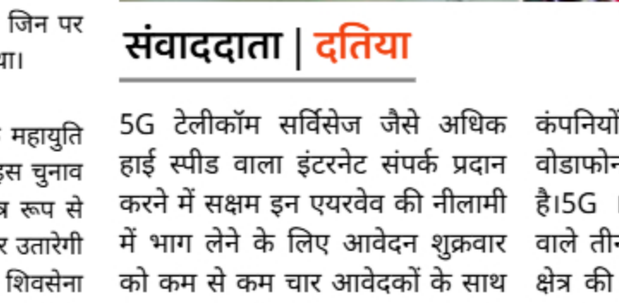

पहले तय सीट-वाटप में भाजपा 50 और शिवसेना 37 वार्डों में चुनाव लड़ेगी, लेकिन आख़िरकार युती नहीं बन सकी। इससे स्थानीय राजनीति में विरोधियों को भी मौका मिला है।

पुणे महापालिका चुनाव में भी सीट-शीयरिंग को लेकर सहमति न बनने के कारण युती प्रभावित हुई है। भाजपा ने शिंदेसेना को 16-17 सीटों का प्रस्ताव रखा, जबकि शिंदेसेना ने कम से कम 25 सीटें की मांग की थी। बातचीत विफल रहने पर शिंदेसेना ने निर्णय लिया कि वह PMC में स्वबळ पर चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवारों को AB फॉर्म वितरित करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इन मतभेदों के चलते महायुति की स्थानीय इकाइयों में अनुसंधान और संगठनात्मक दबाव बढ़ सकता है और यह स्थितियां विरोधी दलों के लिए भी सत्ता में मददगार साबित हो सकती हैं। छत्रपति संभाजीनगर और पुणे दोनों शहरों में भाजपा-शिंदेसेना के बीच न सिर्फ सीट-वाटप को लेकर तकरार है, बल्कि दोनों पक्षों का विरोधात्मक बयानबाजी भी जारी है, जिससे आगामी 15 जनवरी को होने वाले चुनाव नतीजों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

चुनावी माहौल और गठबंधन की इस दरार की खबरों ने स्थानीय मतदाता समुदाय में उत्साह और राजनीतिक चर्चाओं को और अधिक तेज कर दिया है, जो महाराष्ट्र के नगरपालिकाओं की राजनीतिक तस्वीर को और अधिक जटिल बना रहा है।

नागपुर चुनाव: माँ के अंतिम संस्कार के बीच AB फॉर्म मिला, नामांकन समय पर दाखिल

संवाददाता |

नागपुर। नागपुर महानगरपालिका चुनाव 2026 के नामांकन की अंतिम तारीख के दिन एक बेहद भावुक और अनोखी घटना सामने आई है। शिंदे-गुट शिवसेना के योगेश गोन्नाडे जिनकी मां का सोमबार को निधन हो गया था, उन्हें अंत्यसंस्कार के दौरान ही उनके पार्टी नेताओं द्वारा एबी-फॉर्म सौंपा गया, जिससे वे आखिरी समय पर नामांकन दाखिल कर पाए।

गोन्नाडे, जो लंबे समय तक नगरसेवक रहे हैं और एक पूर्व विद्यालय प्रमुख भी हैं, पहले यह सोच चुके थे कि मातृशोक के कारण चुनाव लड़ने का मौका खो देंगे। लेकिन अंतिम संस्कार स्थल पर उन्हें यह महत्वपूर्ण फ़ॉर्म मिलने के बाद उन्होंने समय सीमा से कुछ मिनट पहले सतरंजीपुरा ज़ोन कार्यालय में प्रभाग-5 से नामांकन दाखिल किया।

दुख के बीच यह सहायता पाने को उन्होंने अपनी दिवंगत मां का आशीर्वाद बताया। उनके परिवार के लिए यह क्षण न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, बल्कि भावनात्मक रूप से गहरा भी रहा।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स

Wednesday 31st December 2025 वर्ष - 9 , अंक 245, पृष्ठ 04

मराठवाड़ा में महायुति गठबंधन में दरार: संभाजीनगर के बाद जालना, नांदेड और परभणी में भी भाजपा-शिंदे सेना-राकांपा अलग-अलग लड़ेंगे

मराठवाड़ा, 30 दिसंबर 2025:
2026 के महापालिका चुनावों से पहले मराठवाड़ा में सत्तारूढ़ महायुति (भाजपा-शिंदे सेना-राकांपा) गठबंधन में गंभीर दरार देखी जा रही है। आज महानगरपालिका चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख होने के बीच, गठबंधन में शामिल प्रमुख दलों ने कई नगर निगमों में साझा टिकट पर सहमति नहीं बना पाई है, जिससे गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है।

छत्रपती संभाजीनगर में सीट-बंटवारे को लेकर विवाद के बाद भाजपा और शिंदे सेना के बीच युती टूट चुकी है। इसी तरह जालना, नांदेड और परभणी नगर निगमों में भी भाजपा, शिंदे सेना और राकांपा-अजित पवार गुट ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।

स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच टिकट वितरण और सीट-वाटप को लेकर असंतोष बढ़ गया है। संभाजीनगर में तिकीट न मिलने पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद शिंदे सेना ने युति टूटने की घोषणा की। इसके बाद अन्य शहरों में भी गठबंधन के बजाय स्वबळ पर चुनाव लड़ने का रास्ता चुना गया है।

उधर, राकांपा (अजित पवार गुट) ने भी महायुति में अपेक्षित हिस्सेदारी न मिलने पर कई महानगर पालिकाओं में स्वतंत्र लड़ने का निर्णय लिया है। परभणी में दोनों राकांपा गुट (शरद पवार और अजित पवार) भी गठबंधन न बनाकर मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं।
इस राजनीतिक परिदृश्य से स्पष्ट है कि मराठवाड़ा के नगर निगम चुनाव 2026 में महायुति के साझे फ्रंट की जगह अब अलग-अलग मोर्चों पर तीव्र मुकाबला देखने को मिल सकता है।

NWMC ELCTION | नांदेड मनपा चुनाव 2026

नांदेड मनपा चुनाव: हैदरबाग, खडकपुरा और जयभीमनगर में भाजपा निरंक, तीन प्रभागों में 'आघाड़ी' का राजनीतिक प्रयोग

नांदेड | नांदेड महानगरपालिका चुनाव के मद्देनज़र शहर की राजनीति में नए समीकरण उभरकर सामने आ रहे हैं। बिलोली और धर्माबाद नगर परिषद चुनाव में सफल माने गए आघाड़ी प्रयोग को अब मनपा चुनाव में भी आंशिक रूप से अपनाया जा रहा है। हैदरबाग, खडकपुरा और जयभीमनगर जैसे तीन अहम प्रभागों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आगामी एक-दो दिनों में इस फैसले का वास्तविक राजनीतिक असर स्पष्ट होने की संभावना है।

जिले की राजनीति में जहां एक ओर दलों की अपनी संगठनात्मक मशीनरी सक्रिय है, वहीं दूसरी ओर आघाड़ी के प्रयोगों ने सियासी हलकों में नई चर्चा को जन्म दिया है। हाल ही में धर्माबाद और बिलोली नगर परिषद चुनाव में 'मराठवाड़ा जनहित पार्टी' के नाम से गठित आघाड़ी का प्रयोग किया गया था। इन दोनों शहरों में भाजपा की सांगठनिक पकड़ पहले से मजबूत मानी जाती थी, इसके बावजूद वहां आघाड़ी का सहारा लिया गया। इस प्रयोग को भले ही चुनावी सफलता मिली हो, लेकिन इससे उन क्षेत्रों में भाजपा के स्वतंत्र अस्तित्व पर सवाल खड़े हुए हैं। इसी पृष्ठभूमि में नांदेड शहर के कुछ प्रभागों में भी भाजपा को राजनीतिक रूप से असहज माहौल का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण महानगरपालिका चुनाव में कुछ प्रभागों में आघाड़ी के सहारे चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई गई है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि प्रभाग क्रमांक 7 (जयभीमनगर), प्रभाग क्रमांक 11 (हैदरबाग) और प्रभाग क्रमांक 18 (खडकपुरा-देगांवचाळ) में भाजपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसके अलावा प्रभाग 14 में भी भाजपा की ओर से केवल एक उम्मीदवार मैदान में है। इन प्रभागों में आघाड़ी द्वारा चुनाव लड़े जाने की चर्चा तेज है और माना जा रहा है कि यहां का राजनीतिक वातावरण आघाड़ी के पक्ष में अनुकूल हो सकता है।

प्रभाग 7 में नई आघाड़ी

प्रभाग 7 में 'नांदेड शहर विकास आघाड़ी' का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व विठ्ठल पाटील डक कर रहे हैं। इस आघाड़ी ने सुभाष रायबोले, अभिलाष कदम, मनीष कांबळे और मुंतजीबोद्दीन की मातोश्री को उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल यह आघाड़ी केवल इसी प्रभाग से चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन शहर के अन्य प्रभागों में कई अपक्ष उम्मीदवारों को समर्थन दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

बिलोली पैटर्न की झलक

नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन राजनीतिक गतिविधियां चरम पर रहीं। सभी दलों के नेता और इच्छुक उम्मीदवार सक्रिय नजर आए। जिन उम्मीदवारों को अपने दल से निराशा हाथ लगी, उन्होंने अंतिम समय में जिस पार्टी से बी-फॉर्म मिला, उसी का झंडा थाम लिया। कुछ समय तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन किस दल के साथ है, लेकिन शाम होते-होते इस राजनीतिक जत्रा की तस्वीर साफ हो गई। कुल मिलाकर, नांदेड मनपा चुनाव में इस बार भी 'बिलोली पैटर्न' की झलक और आघाड़ी प्रयोग निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

नांदेड मनपा चुनाव: भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस-VBA का गठबंधन

नांदेड। नांदेड महानगरपालिका चुनाव से ठीक एक दिन पहले राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) ने भाजपा को रोकने के उद्देश्य से गठबंधन करने का निर्णय लिया है। राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि पर हुई बैठक में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी। समझौते के तहत कांग्रेस 61 सीटों पर, जबकि VBA 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

कांग्रेस के निरीक्षक माणिकराव ठाकरे ने बताया कि यह गठबंधन धर्मनिरपेक्ष मतों के बंटवारे को रोकने और भाजपा को सीधी चुनौती देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य सहयोगी दलों से कोई प्रस्ताव न मिलने के कारण यह फैसला लिया गया। गठबंधन के ऐलान के बाद नांदेड में भाजपा और कांग्रेस-VBA के बीच सीधा मुकाबला तय माना जा रहा है।

नांदेड चुनाव ड्रामा: भाजपा टिकट न मिलने पर नाराज़ प्रत्याशी ने हटाए अशोक चव्हाण के फोटो

नांदेड (महाराष्ट्र) — नांदेड महानगरपालिका चुनाव 2026 के अंतिम नामांकन चरण में एक नाटकीय घटना सामने आई है। भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने पर रविंद्र सिंह बुंगई नामक प्रत्याशी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बुंगई ने अपने घर और कार्यालय से पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण के फोटो हटा दिए, यह दर्शाता है कि उन्होंने टिकट न मिलne पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। बुंगई ने यह कदम उस समय उठाया जब पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी नहीं दी और दूसरे मंच से अपना चुनावी सफर तय करने का मौका दिया।

बुंगई, जो 30 वर्षों से चव्हाण के साथ काम कर रहे थे, पहले भाजपा के टिकट के लिए अपेक्षित उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका नाम शामिल नहीं किया। नाराज़गी में उन्होंने चव्हाण के फोटो हटाकर स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपनी नाखुशी को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना चाहते हैं।

इसके बाद उन्होंने शिवसेना (शिंदे गुट) के तत्त्वावधान में प्रभाग 17 से उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। यह बदलाव स्थानीय राजनीति में अप्रत्याशित मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से भाजपा समर्थक कार्यकर्ता ने अपनी राजनीतिक दिशा बदल दी है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह घटना न केवल भाजपा के टिकट वितरण निर्णय पर सवाल उठाती है, बल्कि चुनाव के अंतिम दिनों में उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते असंतोष का संकेत भी देती है। स्थानीय स्तर पर मतदाता और कार्यकर्ता दोनों इस घटना को उत्सुकता से देख रहे हैं, क्योंकि यह चुनाव नतीजों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है।
उम्मीदवारी के अंतिम दिनों में इस तरह की राजनीति और प्रतिक्रियाएँ यह दर्शाती हैं कि नांदेड चुनाव में स्थानीय हित, नेता-कार्यकर्ता रिश्ते और पार्टी निर्णय सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं से चुनावी माहौल और अधिक संवेदनशील तथा सक्रिय बनता जा रहा है।

उत्तर से आई शीतलहर से नांदेड में बढ़ी ठंड, न्यूनतम तापमान 11°C तक गिरा

संवाददाता |

नांदेड, 30 दिसंबर 2025: उत्तर भारत से आई तेज शीतलहर के प्रभाव से नांदेड जिले में क ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे नागरिकों को कड़क ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार (29 दिसंबर) को शहर में न्यूनतम तापमान केवल 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान भी अपेक्षित वृद्धि नहीं दिखा।

हवामान विभाग के अनुसार उत्तरेकडील शीतलहर और उच्च वायुदाब की परिस्थितियों के कारण निरभ्र आकाश तथा शुष्क वायु की वजह से रात का तापमान और अधिक गिर रहा है। आगामी दिनों में भी तापमान 10 डिग्री के आसपास ही रहने की संभावना है।

परभणी के वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ के हवामान विभाग के विशेषज्ञों ने बताया है कि अगले लगभग छह दिनों तक ठंड का असर बना रह सकता है, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ खेतों में काम करने वाले शेतकऱ्यों को भी ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ेगा।

शहर की बाजारें सायं-संध्या के समय शांत नजर आ रही हैं और लोग अधिकतर घरों के भीतर ही रहना पसंद कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों को गर्म कपड़े पहनने और रात में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

टि.सी.हरवली आहे

माझी आप्सरजहाँ शेख अहेमद या नावाची जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,दुधड तालुका हिमायतनगर जिल्हा नांदेड या शाळेची 4 थी ची टि.सी. हिमायतनगर ते निजामाबाद एस टी बस ने प्रवासात गहाळ झाली आहे. कोणास सापडल्यास खालील पत्यावर आणून द्यावी. आणून देणाऱ्यास योग्य ते बक्षिस देण्यात येईल.

संपर्क करें
आप्सरजहाँ शेख अहेमद
C/O शेख हमीद शेख वहीद,
रा.ऑटो नगर, निजामाबाद
ता.जि. निजामाबाद
मो. नंबर (+91 9676103155)

लातूर महानगरपालिका चुनाव: कांग्रेस-वंचित बहुजन आघाड़ी की नई युति, महायुति में दरार से बहुकोणीय मुकाबला तय

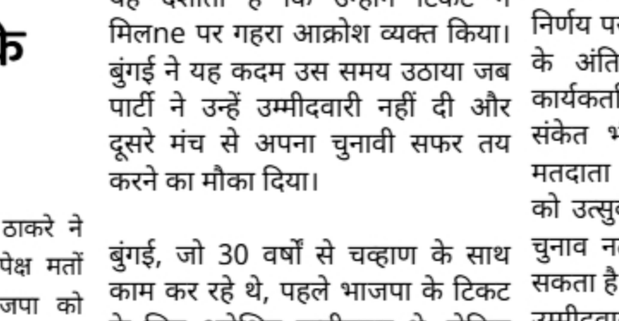

लातूर (महाराष्ट्र)। लातूर महानगरपालिका चुनाव 2026 के समीकरण में ताज़ा मोड़ आया है जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वंचित बहुजन आघड़ी (VBA) ने आख़िरी क्षण में गुप्त गठबंधन का फॉर्मूला अंतिम रूप दिया है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस 65 सीटों पर जबकि VBA 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे मत विभाजन को रोकने की योजना बनाई गई है। इस प्रकार का रणनीतिक तालमेल स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
वहीं दूसरी ओर, भाजपा-नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन में विभाजन की खबरें सामने आ रही हैं। महायुति के भीतर सीट-वाटप पर सहमति न बनने के कारण मुख्य घटक दल —भाजपा, शिंदेसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) — अलग-अलग मैदान में उतरने को तैयार हैं, जिससे इस बार लातूर में चौरंगी-पंचरंगी मुकाबला देखने को मिल सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस-VBA की यह नई 'केमिस्ट्री' भाजपा-नेतृत्व वाली महायुति के विभाजन के समय कांग्रेस को कड़ी चुनौती पेश करने का अवसर दे सकती है। दोनों तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा और प्रचार अभियान तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे स्थानीय मतदाताओं के सामने चुनावी विकल्प व्यापक रूप से खुल जाएंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह गठबंधन खासकर उन इलाकों में प्रभावी साबित हो सकता है जहाँ कॉर्पोरेट मुद्दों, विकास और सामाजिक न्याय जैसे विषय स्थानीय चुनाव चर्चा का हिस्सा हैं। लातूर महानगरपालिका में चुनाव नतीजे राजनीतिक समीकरणों का महत्वपूर्ण संकेत देंगे कि क्या कांग्रेस-VBA गठबंधन भाजपा-नेतृत्व वाले गठबंधन को चुनौती दे पाएगा या नहीं। इन बदलावों ने लातूर के चुनावी माहौल को गतिशील और अस्थिर कर दिया है, जिससे मतदान तक का समय राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक बन गया है।

परभणी मनपा चुनाव 2026: कांग्रेस-उद्धवसेना की युति, राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुट भी मैदान में

परभणी (महाराष्ट्र)। परभणी महानगरपालिका चुनाव 2026 के लिए राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहाँ कांग्रेस और उद्धवसेना (Uddhav Sena) ने गठबंधन (आघाड़ी) किया है, जबकि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के गुट — अजित पवार और शरद पवार भी अलग-अलग चुनाव लड़ने की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं।

कांग्रेस और उद्धवसेना ने मिलकर स्थानीय स्तर पर आघाड़ी बनाई है, जिसमें उद्धवसेना 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को 20-25 सीटों पर प्रत्याशी मिलेंगे। इस गठबंधन के तहत 12 सीटों पर "मैत्रीपूर्ण लढत" होगी, जहां दोनों दल अपने समर्थित उम्मीदवारों के बीच सौहार्दपूर्ण मुकाबला कर सकते हैं। उद्धवसेना ने कहा है कि यह गठबंधन स्थानीय राजनीति में संतुलन बनाने और भाजपा/शिंदे गुट के संपर्क में मत विभाजन को रोकने का प्रयास है।

साथ ही परभणी में दोनों NCP गुटों — अजित पवार गट और शरद पवार गट — ने संयुक्त रूप से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अजित पवार गुट 57 सीटों पर जबकि शरद पवार गुट 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा, जिससे राष्ट्रवादी दल की एकता दिखती है और महापालिका चुनाव में उनकी भागीदारी मजबूती से दर्ज होगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विविध गठबंधन चुनावी समीकरण को और अधिक जटिल बनाएगा, क्योंकि स्थानीय मतदाताओं के सामने अब विकल्प अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप से मौजूद होंगे। कांग्रेस-उद्धवसेना युति भाजपा/शिंदे गुट के मुकाबले स्थानीय स्तर पर मजबूत चुनौती पेश कर सकती है, वहीं नवनिर्मित NCP संबंध भी वोट विभाजन पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह चुनाव नतीजे आगामी 15 जनवरी 2026 के मतदान के बाद राजनीतिक ताकतों में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देंगे।

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)